

प्रेषक,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

औद्योगिक विकास अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 13 दिसम्बर,
नवम्बर, 2011

विषय: वाणिज्य कर कार्यालय, रुड़की के कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण हेतु राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के परिसर में स्थित अतिरिक्त भूमि में से न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर 10175 वर्ग मीटर भूमि आवंटित करने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आयुक्त कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 4165-आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/सम्पत्ति-अनु0/2011-12/दे0दून, दिनांक 02 नवम्बर, 2011 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वाणिज्य कर कार्यालय, रुड़की के कार्यालय भवन एवं आवास निर्माण हेतु राजकीय मुद्रणालय, रुड़की के परिसर में स्थित अतिरिक्त भूमि में से न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर मौके पर उपलब्ध भूमि की पैमाईश कराकर स्वीकृत सीमा के अन्दर 10175 वर्ग मीटर भूमि वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड शासन को वित्त अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 260/वि0अनु-3/2002, दिनांक 15 फरवरी, 2002 की व्यवस्थानुसार निम्नलिखित शर्तों के अधीन निःशुल्क भूमि हस्तान्तरण की अनापत्ति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. भूमि पर कोई धार्मिक अथवा ऐतिहासिक महत्व की इमारत न हो।
2. जिस परियोजना के लिए भूमि हस्तान्तरित की जा रही है वह एक अनुमोदित परियोजना हो और उसके लिए शासन से सहमति प्राप्त हो चुकी हो।
3. हस्तान्तरित भूमि यदि प्रस्तावित कार्य से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग की जाये, तो उसके लिये मूल विभाग से पुनः अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
4. यदि भूमि की आवश्यकता न हो या 03 वर्षों तक हस्तान्तरित भूमि प्रस्तावित कार्य के लिए उपयोग में नहीं लाई जाती है तो उसे मूल विभाग को वापस करना होगा।
5. जिस प्रयोजन हेतु भूमि हस्तान्तरित की गयी है उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी अन्य व्यक्ति, संस्था, समिति अथवा विभाग को भूमि हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।